

डॉ. यादव और सिधिया कल आएं शिवपुरी

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का करेंगे शिलान्यास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया का 5 जुलाई को शिवपुरी दौरा प्रस्तावित है। शहर के पोला ग्राउंड में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में दोनों नेता करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा के साथ कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा का विस्तार से चर्चा की गई। मंच

व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितग्राहियों एवं आमजन की उपस्थिति को देखते हुए पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल तक लोगों की आवाजाही सुगम रहे तथा पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन पूरी तरह व्यवस्थित हो।

सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को लेकर प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक यांगवेन डोलकर भूटिया के साथ विस्तृत चर्चा की और वीआईपी प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी सुरक्षा इंतजाम मजबूत रखने के निर्देश दिए।



विद्यार्थी हित और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें विश्वविद्यालय : परमार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि ऐसे ज्ञान केंद्र हैं जहां समाज और राष्ट्र के लिए संवेदनशील, नैतिक एवं उत्तरदायी नागरिक तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के

अनुरूप विश्वविद्यालयों को विद्यार्थी हित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, नवाचार और पारदर्शी कार्य संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

शुक्रवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम में मंत्री ने विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से

सीधा संवाद किया। उन्होंने परीक्षा, शोध, छात्रवृत्ति, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, डिजिटल सुविधाओं, प्लेसमेंट और खेल गतिविधियों से जुड़े सुझाव एवं समस्याएं सुनीं तथा अधिकारियों को उनके समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था

विकसित की जाए, जहां प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या का संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ समाधान हो। मंत्री ने कहा कि समय पर प्रवेश, समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की आधारशिला हैं। परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने

के लिए डिजिटल मूल्यांकन तथा ऑनलाइन परीक्षा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राध्यापकों की उपस्थिति के लिए उपयोग किए जा रहे 'सार्थक ऐप' के माध्यम से अब विद्यार्थियों की उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी, जिससे अनुशासन और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

कृषक कल्याण वर्ष में किसानों से होगा सीधा संवाद

खेती की लागत को घटाने और आय बढ़ाने पर सरकार का जोर



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हित में संचालित योजनाओं का मिशन मोड में प्रभावी क्रियान्वयन

सुनिश्चित किया जाए तथा राजधानी से लेकर ग्राम स्तर तक किसानों से सीधे संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों की अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके लिए उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने में निजी संस्थाओं का सहयोग लिया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों का विस्तार किया जाए। उन्होंने किसानों को कम पानी और कम अवधि वाली फसलों के प्रति जागरूक करने, प्राकृतिक एवं

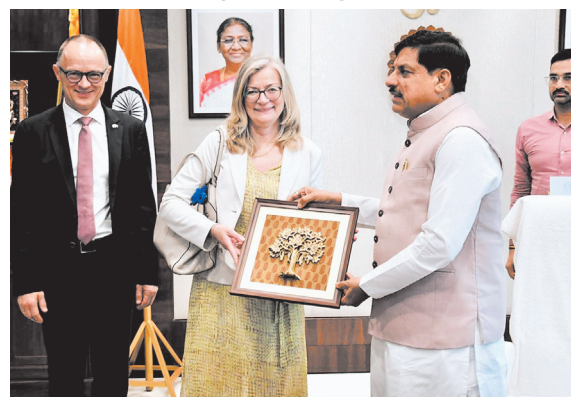
जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा फसल चक्र में बदलाव के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उनके डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि जुलाई में ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और किसानों के लिए ई-पासबुक सुविधा शुरू की जाएगी। साथ ही राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित होगा। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि

महोत्सव तथा सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा खरगोन में किसान सम्मेलन एवं कपास-मिर्च महोत्सव, बुरहानपुर में केला महोत्सव, इंदौर में सब्जी महोत्सव, जबलपुर में मत्स्य पालन एवं कुक्कट सम्मेलन, उज्जैन में हाईटेक नर्सरी कार्यशाला, सागर और रतलाम में एफपीओ सम्मेलन, नौमच में उद्यानिकी कार्यशाला तथा भोपाल में पराली प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित करने की योजना है।

भारत-जर्मनी साझेदारी मजबूत करने में प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को मंत्रालय में जर्मनी के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक में ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और भविष्य की निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक की सीईओ सुश्री क्रिस्टियाने लाईबेक, कंटी डायरेक्टर वूल्फन मूथ, जर्मन दूतावास के प्रतिनिधि गॉटफ्रीड वॉन सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच दशकों पुरानी मित्रता है और दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत



बनाने में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जर्मनी के उद्योगपतियों और निवेशकों के समुद्र राज्य के रूप में आगे ऊर्जा क्षेत्र में केएफडब्ल्यू

डेवलपमेंट बैंक के सहयोग को सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि जर्मनी के सहयोग से मध्यप्रदेश ऊर्जा दक्ष, हरित और समृद्ध राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया

कि एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में स्मार्ट मीटर स्थापना और फोडर विभक्तिकरण के लिए लगभग 1,120 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही बैंक ने एनर्जी रिफॉर्म फेज-2 के अंतर्गत विद्युत वितरण अधोसंरचना के सुदृढीकरण तथा सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि फोडरों को बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक ढांचगत विकास हेतु लगभग 200 मिलियन यूरो के वित्तीय सहयोग में भी रुचि दिखाई है। बैठक में दोनों पक्षों ने भविष्य में ऊर्जा, हरित विकास और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को और व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की।

एमपीपीजीसीएल के कर्मचारियों के लिए सोलर रूफटॉप योजना लागू

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए सोलर रूफटॉप प्लांट योजना लागू की है। इस पहल के तहत कंपनी के कार्मिक अपने आवास पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर सकेंगे, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली खर्च में भी कमी आएगी। इच्छुक कर्मचारी संबंधित विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सूचीबद्ध विक्रेताओं में से अपनी पसंद का विक्रेता चुन सकेंगे। पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। 3 किलोवाट तक क्षमता वाले सोलर रूफटॉप प्लांट की स्थापना पर पात्रता के अनुसार निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत अनुदान विक्रेता को दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना जारी



कृषि और एमएसएमई को प्राथमिकता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5,00,856 करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना जारी की गई है।

शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा तैयार वार्षिक साख योजना का विमोचन करते हुए कहा कि जिला स्तर पर तैयार क्रेडिट प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश की

आर्थिक गतिविधियों को और मजबूती मिल सके। योजना के अनुसार इस वर्ष का ऋण लक्ष्य पिछले वर्ष के 4,19,110 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 19.5 प्रतिशत अधिक रखा गया है। कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फार्म क्रेडिट के लिए 1,28,866 करोड़ रुपये तथा कुल कृषि क्षेत्र के लिए 1,65,117 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं फसल ऋण के लिए 88,638 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे

किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश की उद्योगो-मुखी नीतियों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए 1,62,967 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी ऋण लक्ष्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए कुल 3,45,915 करोड़ रुपये की ऋण व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कुल वार्षिक ऋण योजना का लगभग 69 प्रतिशत है।

कैप्टन पांडेय के बलिदान दिवस पर डॉ. यादव ने दी श्रद्धांजलि

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय के बलिदान दिवस पर विभ्रम श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कैप्टन पाण्डेय का अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के गौरव का अमर अध्याय है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: देवास के खिबनी अभयारण्य में आपसी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए नर बाघ 'युवराज' का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल के रेस्क्यू सेंटर में उपचार जारी है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बाघ को 27 जून को रेस्क्यू कर वन विहार लाया गया था, जहां विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है।

शुक्रवार को राज्य पशु चिकित्सालय जहांगीरबाद के वरिष्ठ वेटरिनरी सर्जन डॉ. एस.के. तुमड़िया, वन विहार के वरिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल गुप्ता और पशु चिकित्सक डॉ. विनोद ने बाघ का विस्तृत



चिकित्सकीय परीक्षण किया। जांच में उसके आगे के दोनों पंजों में फ्रैक्चर तथा पिछले बाएं पैर में गहरा घाव पाया गया, जिस पर छह टांके लगाए गए हैं। चिकित्सकों के अनुसार बाघ की स्थिति पर

लागातार निगरानी रखी जा रही है और स्वास्थ्य के अनुसार उपचार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान वन विहार के संचालक विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

नकली नोट, प्रिंटर मशीन समेत दो आरोपी गिरफ्तार

रंगीन प्रिंटर की मदद से 500 रुपये के नकली नोट तैयार कर रहे थे आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : मध्य प्रदेश के आगरामालवा जिले की नलखेड़ा पुलिस ने गुरुवार की रात बस स्टैंड स्थित एक कृषि सेवा केंद्र की दुकान पर से 500-500 रुपये के कुल 115 नकली नोट जब्त किए, जिनकी कीमत

57,500 रुपये है। कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नलखेड़ा पुलिस थाना प्रभारी नागेश यादव ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कच्चा भ्रमण के दौरान बस स्टैंड चौराहे पर एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंवार कृषि सेवा केंद्र में दो युवक रंगीन प्रिंटर की मदद से 500 रुपये के नकली नोट तैयार कर रहे हैं और उन्हें एक

काले बैग में रखकर किसी को देने की तैयारी में हैं। सूचना को गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और आवश्यक अनुसंधान सामग्री बुलाकर पंचों की उपस्थिति में मुखबिर सूचना का पंचनामा तैयार करने के बाद पुलिस टीम ने कृषि सेवा केंद्र पर दबिश दी।

दुकान में मौजूद युवकों की पहचान ग्राम पिपल्यासेत निवासी नरेंद्रसिंह (23) और नलखेड़ा निवासी शुभम सोलंकी (27) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान, नरेंद्र के काले बैग से 500-500 रुपए के 115 नकली नोट बरामद हुए। जांच में पाया गया कि कई नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था, जिससे उनके नकली होने की पुष्टि हुई। पृष्ठताड़ में आरोपियों ने बताया कि वे कैनन रंगीन प्रिंटर से असली नोटों की रंगीन कॉपी

बनाते थे और फिर पेपर कटर से काटकर नकली नोट तैयार करते थे। पुलिस ने मौके से कैनन कंपनी का रंगीन प्रिंटर, पेपर कटर और दोनो आरोपियों के कब्जे से एक-एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त कर विधिवत सीलबंद कर आरोपियों को धारा 178 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

नुसार, 7 जून को आरोपित महिलाअपनी मां के साथ उसके घर पहुंची और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग और बैंक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज साक्ष्य के रूप में सौंपे हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपित महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच कर मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।

रीवा का श्रीरामानुज संस्कृत परिसर बनेगा वैदिक अध्ययन और शोध का प्रमुख केंद्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा स्थित श्रीरामानुज संस्कृत परिसर को संस्कृत, वैदिक अध्ययन, भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन-अध्यापन तथा शोध का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। शुक्रवार को मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के परिसर के सशक्तीकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने और शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार पर जोर दिया। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर

चर्चा हुई। इनमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर-शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन पदों की पूर्ति अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध मार्गदर्शन तथा आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक वातावरण विकसित होगा।

अपराध पूर्व घरेलू सहायिका पर पीएचई कर्मचारी को ब्लैकमेल करने, झूठे दुष्कर्म केस में फसांने की धमकी देने का आरोप...

निजी वीडियो से एक करोड़ रुपए की रंगदारी का आरोप

डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई

हनीट्रैप मामले में महिला गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कथित हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीएचई विभाग में कार्यरत एक युवक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तीन बच्चों की मां और पूर्व घरेलू सहायिका के खिलाफ एक करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने, निजी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और धमकी देने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, शहर के वेदांत भवन निवासी 31 वर्षीय मोहित मांझी ने



शिकायत में बताया कि आरोपित महिला उसके घर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। इस दौरान उसने अपनी

आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां उसके घर घरेलू सहायिका को रूप में काम बताने सहानुभूति हासिल की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने कई

बार महिला और उसके कहने पर उसके भाई-भाभी के खातों में भी आर्थिक मदद के रूप में राशि ट्रांसफर की। शिकायत में कहा गया है कि बाद में दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध बने। इसी दौरान महिला ने कथित रूप से बिना जानकारी के उनके निजी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद उसने व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजकर उन्हें सार्वजनिक करने और दुष्कर्म के झूठे आरोपों से परेशान होकर उसे अपना निवास तक बदलना पड़ा, लेकिन महिला ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शिकायत के

नुसार, 7 जून को आरोपित महिलाअपनी मां के साथ उसके घर पहुंची और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग और बैंक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज साक्ष्य के रूप में सौंपे हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपित महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच कर मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।